

With this background, I take this privilege to request the Government of India to kindly examine the proposal of the State Government for early inclusion of these three languages in the list of Eighth Schedule of the Constitution on top priority.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Dorjee Tshering Lepcha: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Khiru Mahto (Bihar) and Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

**Demand to include traditional kitchen tips for home remedies in education system of the country**

**डा. कल्पना सैनी** (उत्तराखण्ड) : उपसभापति महोदय, मैं आपके समक्ष एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह विषय हमारे स्वास्थ्य, परंपरा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज के आधुनिक दौर में हम अपने पारंपरिक रसोई नुस्खों को भूलते जा रहे हैं। हम छोटी-छोटी बीमारियों और तकलीफों के लिए दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जबकि हमारी भारतीय रसोई हमेशा प्राकृतिक औषधियों का खजाना रही है।

मान्यवर, हमारी रसोई में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक मसाले केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी का काम भी करते हैं। उदाहरण के रूप में हल्दी, अदरक और लहसुन प्राकृतिक एंटीबायोटिक हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। मेथी, जीरा और धनिया में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज और फाइबर होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं। हींग और अजवाइन पेट की समस्याओं का रामबाण इलाज है। लहसुन और दालचीनी हृदय को स्वस्थ रखने, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हैं।

उपसभापति महोदय, हम पारंपरिक नुस्खों को अपनाकर हम अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर बना सकते हैं, डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये नुस्खे हमें केवल स्वस्थ ही नहीं रखते, बल्कि पर्यावरण को संरक्षित करने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि इनमें प्राकृति और जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि परंपरागत रसोई नुस्खों को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए, स्कूल्स और कॉलेजों में खाना पकाने के व्यावहारिक सत्र आयोजित किए जाएं और छात्र-छात्राओं को सिखाया जाए कि किस प्रकार पारंपरिक नुस्खों का उपयोग करके वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। प्राकृतिक और जैविक खाद पदार्थों के महत्व को समझाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

उपसभापति महोदय, हमारे पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान दिया है, उसे संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने पारंपरिक मसालों और नुस्खों को शिक्षा का हिस्सा बनाएंगे, तो हम आने वाली पीढ़ियों को बीमारी से बचाने, उन्हें पोषण देने और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में सफल होंगे। यह प्राकृतिक और टिकाऊ स्वास्थ्य की ओर एक क्रांतिकारी कदम होगा, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Kalpana Saini: Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Dr. Faiyaz Ahmad (Bihar), Dr. Sangeeta Balwant (Uttar Pradesh), Shri Rwngrwa Narzary (Assam), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), and Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sanjay Seth. Not present. Shri Pramod Tiwari.

### **Need to address the problem of substandard medicines in the country**

**श्री प्रमोद तिवारी** (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, बाजार में बढ़ती हुई घटिया दवाओं के संदर्भ में मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि उन्होंने जांच में पाया कि देश में बिक रही 50 दवाइयों के नाम दिए हैं। ये दवाइयाँ घटिया स्तर की बन रही हैं। इसमें पैरासिटामोल से लेकर ब्लड प्रेशर, खांसी, मल्टी विटामिन्स और कैल्शियम की दवाएं शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं।

महोदय, देश में घटिया और नकली दवाओं का जाल फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में घटिया दवाओं की अधिक चुनौतियाँ हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे दवा निर्माताओं द्वारा निर्मित 15 प्रतिशत से अधिक दवाइयाँ गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही हैं। छोटे दवा निर्माता ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करते हैं। महोदय, घटिया दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। घटिया दवाओं के सेवन से मृत्यु हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार उत्पादित की जा रही दवाओं में 12-25 प्रतिशत तक मिलावटी, घटिया या नकली दवाएं हो सकती हैं। 2023 में 'जन विश्वास विधेयक' में किए गए संशोधन के नियम 27 (डी) के तहत मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) के तहत न होने वाली दवाओं की सजा को कंपाउंडिंग अपराधों में कंवर्ट करने की अनुमति दी गई है। सर, वे लोग सजा को कंपाउंडिंग अपराध में परिवर्तित करा देते हैं, इसलिए यह इतना बढ़ रहा